दैनिक जागरण

ध्यान की दौलत से कार्य करने की क्षमता अपने आप बढ़ती है

ट्रंप से खरी बात

फ्रांस के बायरिट्ज शहर में भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष जिस तरह दो टूक ढंग से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सारे मसले द्विपक्षीय हैं और इसीलिए हम किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते उससे ट्रंप प्रशासन को यह पता चल जाना चाहिए कि आज के भारत को कश्मीर या फिर किसी अन्य मसले पर झुकाया नहीं जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष खरी बात करने की जरूरत इसलिए थी, क्योंकि हाल में उनकी ओर से दो-तीन बार यह कहा जा चुका है कि वह कश्मीर पर मध्यस्थता करने को तैयार हैं। उनके ऐसे बयानों से ही पाकिस्तान अपनी पीठ ठोकने में लगा हुआ था। अब उसे भी यह अहसास हो जाए तो बेहतर कि अमेरिका या फिर चीन का सहारा लेकर वह भारत को आंखें नहीं दिखा सकता। यह उल्लेखनीय है कि इसके पहले भारत ने चीन के समक्ष भी यह साफ कर दिया था कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से न तो पाकिस्तान से लगती सीमा में कोई बदलाव हुआ है और न ही चीनी सीमा में। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री की खरी बात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति भी यह कहने को बाध्य हुए कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर समस्याओं को सुलझा लेंगे, लेकिन भारत सरकार को केवल इतने से ही संतोष नहीं करना चाहिए। चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी मसले पर कुछ भी कहने और यहां तक कि अपनी ही बातों से मुकर जाने में माहिर हैं इसलिए भारत को चाहिए कि वह अमेरिकी विदेश विभाग से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा वक्तव्य को आधिकारिक रूप देने की मांग करे।

यह आवश्यक है कि भारत सभी आवश्यक मंचों पर यह भी स्पष्ट करे कि वह कश्मीर पर मध्यस्थता का राग सुनने को इसलिए नहीं तैयार, क्योंकि यह उसका अपना आंतरिक मामला है और अगर पाकिस्तान से कोई बात होती है तो वह उसके कब्जे वाले भारतीय भूभाग को लेकर ही होगी। यह सही समय है कि भारत इस बात को भी पूरी दृढ़ता के साथ रेखांकित करे कि पाकिस्तान या फिर अन्य किसी देश को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि भारत जम्मू-कश्मीर या फिर लद्दाख को लेकर किसी से वार्ता करने को राजी हो सकता है। वास्तव में ऐसा करने पर ही दुनिया को यह संदेश जाएगा कि कश्मीर का असल विवाद तो पाकिस्तान के कब्जे वाले उस भारतीय भूभाग को लेकर है जिसे पाकिस्तान ने हथिया रखा है। देश के राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग को भी यह समझने की जरूरत है कि कश्मीर को लेकर रक्षात्मक रवैया अपनाने के कारण ही पाकिस्तान दुनिया में भ्रम फैलाने में कामयाब रहा।

सोनिया की हरी झंडी

बंगाल में कांग्रेस और माकपा समेत वाममोर्चा के अन्य घटक दलों की स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसे में कांग्रेस एवं वामदल एक दूसरे के सहारे भाजपा को रोकने की कोशिश में लगे हैं। यही वजह है कि विधानसभा उपचुनाव की घोषणा से पहले ही वामदलों से साथ गठबंधन करने को बंगाल के पार्टी नेताओं को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरी झंडी दे दी। यही नहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में भी वामदलों के साथ लड़ने की सोनिया गांधी ने मंजूरी दे दी है। सोनिया ने बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा के साथ बैठक की जिसमें गठबंधन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद सोमेन मित्रा ने कहा कि अंतरिम अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि अगर वाममोर्चा तैयार है तो दोनों पक्षों को राज्य में गठबंधन कर लेना चाहिए। भाजपा को रोकने के लिए तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा सभी विपक्षी दलों के एक हो जाने के आह्वान के मद्देनजर सोनिया गांधी का यह फैसला काफी अहम है। हालांकि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता की मानें तो ममता के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्तों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने बंगाल में गठबंधन के लिए वामदलों का चुनाव किया है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि 2021 का विधानसभा चुनाव राज्य की तृणमूल सरकार के खिलाफ होगा। ऐसे में सिर्फ भाजपा विरोध के नाम पर हम तृणमूल के साथ नहीं जा सकते। कांग्रेस एवं माकपा नेतृत्व के बीच तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर सहमति बन गई है। उत्तर दिनाजपुर की कालियागंज एवं पश्चिम मेदिनीपुर की खड़गपुर सीट पर कांग्रेस, जबकि माकपा नदिया जिले के करीमपुर सीट से लड़ेगी। कालियागंज सीट कांग्रेस विधायक प्रमथनाथ राय की मौत के बाद खाली हुई है। जबकि खड़गपुर सीट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष विधायक थे। उनके मेदिनीपुर से सांसद बनने के बाद वह सीट खाली हुई है। इसी तरह करीमपुर से तृणमूल की विधायक रही महुआ मोइत्रा अब कृष्णानगर से सांसद हैं। इसकी वजह से वह सीट खाली हुई है। इससे पहले कांग्रेस एवं वाममोर्चा ने 2016 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ा था। हालांकि उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 के लिए उनके बीच सीट बंटवारे पर मामला फंस गया था। इसके बाद दोनों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा। दोनों का ही प्रदर्शन प्रदेश में बदतर रहा। कांग्रेस जहां मात्र दो सीट जीत सकी, जबकि 38 सीटों पर उसके प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। वामो के हिस्से बंगाल से एक भी सीट नहीं आई।

ताशकंद और शिमला समझौते के सबक

सुरेंद्र किशोर

चूंकि शिमला में एक तरह से ताशकंद ही दोहराया गया इसलिए यह जरूरी है कि मौजूदा सरकार इन दोनों समझौतों से सबक सीखे

अवधेश राजपूत

जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में मोदी सरकार की ओर से लिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद से शिमला समझौता की व्यापक चर्चा हो रही है। 3 जुलाई, 1972 को हुए इस समझौते के बारे में यह बात कम लोग ही जानते हैं कि उसकी धज्जियां पाकिस्तान के तत्कालीन शासक जुल्फीकार अली भुट्टो ने उसी जुलाई महीने में ही उड़ानी शुरू कर दी थी। इसीलिए यह कहा जाता है कि भारतीय सेना ने तो युद्ध में फतह हासिल की, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने समझौते की मेज पर सेना द्वारा हासिल लाभ गंवा दिया। ताशकंद समझौते में भी ऐसा ही हुआ था। ताशकंद समझौते के खिलाफ केंद्रीय मंत्री महावीर त्यागी ने अपना इस्तीफा तक दे दिया था। वह ताशकंद समझौते की कुछ शर्तों से असहमत थे। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। शास्त्री मंत्रिमंडल के सारे सदस्य नंदा मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिए गए। जब ताशकंद समझौते पर मुहर लगाने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो बहुत देर तक ताशकंद समझौते पर विवाद होता रहा। महावीर त्यागी ने लिखा है, 'जब इस समझौते को स्वीकार करने का प्रस्ताव आया तो मैं कैबिनेट छोड़कर बाहर आ गया और अपना त्यागपत्र नंदा जी के पास भेज दिया।' अपने इस्तीफे के बाद त्यागी जी ने कहा कि उनकी समझ से पाकिस्तान और भारत तब तक अच्छी तरह उन्नत और संपन्न नहीं बनेंगे जब तक इन दोनों देशों में एकता स्थापित नहीं हो जाती। उन्होंने लिखा कि ताशकंद समझौते के मूल ध्येय से भी मैं सहमत हूं, लेकिन इस समझौते की कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी सरकार और हमारी पार्टी की ओर से की गई घोषणाओं के विपरीत हैं। इस समझौते के कई तत्व बहुत ही गंभीर हैं। केवल भारत के रक्षा मंत्री की हैसियत से ही नहीं, बल्कि विश्व युद्ध के सैनिक की हैसियत से मेरे कुछ निजी अनुभव हैं। उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जीती हुई हाजी पीर की चौकियों को छोड़ना भयंकर भूल होगी, विशेष कर तब जब पाकिस्तान अपने छापामारों, गुप्तचरों और बिना वर्दी के हथियारबंद सैनिकों को वापस बुलाने और भविष्य में ऐसे आक्रमण न करने को कटिबद्ध नहीं होता।

महावीर त्यागी ने यह भी लिखा है कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद पाकिस्तानी नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि 'समझौते में हथियारबंद पाकिस्तानियों को वापस बुलाने का जो जिक्र है उसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने हथियारबंद छापमारों को भी कश्मीर से वापस बुलाएंगे। इसी तरह एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का अर्थ यह नहीं है कि हम जम्मू-कश्मीर में कोई दखल न दें, क्योंकि इस क्षेत्र को पाकिस्तान अपना निजी क्षेत्र मानता है।'

ताशकंद समझौते जैसा हश्र शिमला समझौते का भी हुआ। शिमला समझौते पर दस्तखत करके पाकिस्तान लौटने पर पाकिस्तानी संसद में अपने 165 मिनट के भाषण में भुट्टो ने कहा था, 'हम पाकिस्तान की जनता की ओर से यह आश्वासन देना चाहते हैं कि ज्यों ही कश्मीर की जनता अपना मुक्ति आंदोलन शुरू करती है, पाकिस्तान के लोग उनकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। वे इस सिलसिले में अपना खून बहाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे।' पाकिस्तान के युद्धबंदियों पर भुट्टो का कहना था कि 'भारत उन्हें अधिक देर तक नहीं रख सकता। हम इस सिलसिले में विश्व जनमत बनाने का प्रयास करेंगे।' भुट्टो ने यह भी कहा, 'इस समझौते से कश्मीर के बारे में हमारे किसी प्रकार के सिद्धांतों का हनन नहीं हुआ है। पाकिस्तान कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने को स्वतंत्र है।'

शिमला समझौते के समय अटल बिहारी वाजपेयी शिमला में ही थे। समझौते के बाद वाजपेयी ने जो कुछ कहा, इतिहास ने उसे सच साबित किया। वाजपेयी ने तभी कह दिया था, 'यह भारत का आत्मसमर्पण है, क्योंकि दोनों देशों के विवादों पर कोई समझौता न होने पर भी भारत पाकिस्तानी इलाकों से भारतीय सेनाओं को हटा लेने पर सहमत हो गया।' याद रहे कि समझौते के अनुसार पाकिस्तान को 69 वर्ग मील भारतीय इलाका खाली करना था तो भारत को 5139 वर्ग मील पाकिस्तानी इलाका। शिमला समझौते पर तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह का कहना था कि दोनों देशों ने भारतीय उप महाद्वीप में स्थायी शांति की स्थापना के उद्देश्य से बातचीत में भाग लिया, लेकिन सब जानते हैं कि शांति स्थायी रूप नहीं ले सकी। यदि ताशकंद और शिमला में भारत ने पाकिस्तान से कड़ी सौदेबाजी की होती तो स्थायी शांति की जमीन तैयार हो सकती थी। ध्यान रहे ताशकंद समझौते के जरिये भी भारत ने जीती हुई महत्वपूर्ण भूमि पाकिस्तान को लौटा दी थी। उसी जमीन से घुसपैठिये लगातार कश्मीर में प्रवेश करके आतंक फैलाते रहे।

पाकिस्तान हर बार गैर भरोसमंद पक्षकार ही साबित हुआ है। वह झूठ बोलने और अपने लोगों समेत दुनिया को भरमाने में माहिर है। यह किसी से छिपा नहीं कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक पर उसका यही कहना था कि भारत चंद पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ खास नहीं कर सका। अब यह कह रहा है कि भारत बालाकोट से भी बड़े हमले की तैयारी में है। शिमला समझौते के तहत दोनों देशों ने संकल्प लिया था कि वे अपने मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण उपायों से हल करेंगे और दोनों देशों की सरकारें अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक-दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार नहीं करेंगी। इसमें यह भी कहा गया था कि आपसी संबंधों में सामान्य स्थिति लाने की दृष्टि से सुविधाओं का आदान-प्रदान होगा और दोनों देशों की सेनाएं अपनी सीमा में लौट जाएंगी। समझौते का एक बिंदु यह भी था कि जम्मू-कश्मीर में 17 दिसंबर, 1971 को हुए युद्ध विराम के तहत नियंत्रण रेखा को मान्य रखेंगे। इस समझौते को लागू करने के लिए किसने क्या प्रयास किए, इसे बयान करने के लिए 1972 के बाद की घटनाएं पर्याप्त हैं। कश्मीर में आतंक फैलाए रखने में पाकिस्तान की मुख्य भूमिका रही है। वह वहां खुले आम जिहाद छेड़ने की बात करता है।

कश्मीर में पाकिस्तान की बेजा हरकतें भारत की ओर से उसके प्रति दिखाई गई उदारता का नतीजा हैं। क्या शिमला समझौते में शामिल भारतीय पक्ष ताशकंद समझौते के बाद के अनुभव से परिचित नहीं था? जरूर परिचित रहा होगा। 90 हजार सैनिकों और करीब 5 हजार वर्ग मील पाकिस्तानी भूभाग पर भारतीय सेना के कब्जे के बावजूद भारत सरकार पाकिस्तान को कोई ठोस सबक नहीं सिखा सकी। शिमला में एक तरह से ताशकंद दोहराया गया। यदि अब ऐसा कोई अवसर आए तो यही उम्मीद की जाती है कि मौजूदा सरकार ताशकंद और शिमला वाली गलती नहीं करेगी। इसी के साथ यह भी उम्मीद की जाती है कि हमारी सरकार उस पुरानी धारणा से भी इस देश को मुक्त करेगी कि भारतीय अपने इतिहास से नहीं सीखते।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

सक्षम नौकरशाही को प्रोत्साहन जरूरी

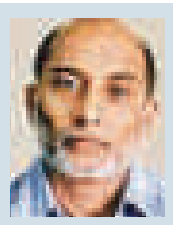

प्रेमपाल शर्मा

जब कुछ अधिकारियों को उनकी प्रतिभा और मेहनत का फल मिलता है तो पूरी नौकरशाही में नई जान पड़ जाती है

पुरस्कार और दंड देने की प्रक्रिया नौकरशाही के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी जीवन के दूसरे पक्षों में। हाल में कर्मठ, ईमानदार और नवोन्मेषी 16 जिला अधिकारियों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके बाद यह खबर आई कि कई टैक्स अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि वे कारोबारियों को अनावश्यक रूप से तंग कर रहे थे। यह सिलसिला कायम रहना चाहिए। बीते दिनों जिन अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया वे देश के अलग-अलग हिस्सों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर अयाज फकीर भाई ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को जन-जन को सुलभ बना दिया तो संदीप नंदूरी ने पानी की कमी से जूझते तमिलनाडु के कई गांवों में बर्बाद पानी को इकट्ठा कर फिर उपयोग में लाने की विधि ईजाद कर दी। वहीं राकेश कंवर ने हिमाचल प्रदेश में कूड़े के ढेर को एक खूबसूरत पार्क में बदल दिया। इसी तरह राजकुमार यादव, माधवी खोडे, कार्तिकेय मिश्रा आदि को जब शिक्षा, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा और मेहनत का फल मिला। जब ऐसा होता है तो पूरी नौकरशाही में नई जान पड़ जाती है और अन्य अधिकारी भी कुछ बेहतर करने को प्रेरित होते हैं। पिछले कुछ दिनों में सरकार की कोशिश बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने की रही है। 2006 में शुरू किए गए सिविल सेवा अवार्ड ने भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिविल सेवा अवॉर्ड हर वर्ष सिविल सेवा दिवस यानी 21 अप्रैल को देश के अलग-अलग क्षेत्रों में शासन-प्रशासन से जुड़े हर स्तर के अधिकारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कामों के लिए दिए जाते हैं। राजस्थान के जिलाधिकारी द्वारा जेनरिक दवाओं की शुरुआत हो या फिर बदायूं के जिलाधिकारी द्वारा मल मुक्ति अभियान, कर्नाटक में भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण करना हो अथवा रेलवे में ई टिकटिंग की व्यवस्था, इसी के चंद उदाहरण हैं।

निःसंदेह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक कड़ी चयन प्रक्रिया से गुजर कर देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं प्रशासनिक सेवाओं में आती हैं। यदि उन्हें लगातार इसी तरह प्रोत्साहन मिलता रहे तो नौकरशाही का चेहरा बदल सकता है। अभी तक के ज्यादातर अनुभव यही बताते हैं कि आजादी के बाद नौकरशाही की कार्यक्षमता में लगातार गिरावट आती गई है और भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, फिजूलखर्ची में बढ़ावा देखने को मिला है। हम सब के निजी अनुभव भी यही बताते हैं और एनएन वोहरा से लेकर प्रशासनिक सुधार आयोग की तमाम रपटें और दूसरे तमाम सर्वे भी इसी ओर इंगित करते हैं, लेकिन कर्मठ अफसरों को प्रोत्साहन के प्रचार-प्रसार से हालात बदले जा सकते हैं। भारतीय नौकरशाही की बहुत बड़ी कमी यह महसूस की जाती रही है कि आप एक बार उसके हिस्से हो जाएं तो आप कुछ करें या न करें या कितना भी अच्छा करें आपको कोई फल नहीं मिलने वाला और न करने पर भी आपके करियर पर कोई असर नहीं होने वाला। इस धारणा को मूल रूप से समाप्त किए जाने की जरूरत है। इन पुरस्कारों की यही भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल पुरस्कार ही नहीं, सरकार को निकम्मे लोगों से मुक्ति भी पानी होगी।

हाल में जिन अधिकारियों की उम्र 55 वर्ष हो चुकी है या जो 25 वर्ष की सेवा कर चुके हैं उनके कार्य निष्पादन का आकलन किया जा रहा है। सरकार के ऐसे कदमों और खासकर नाकारा या भ्रष्ट अधिकारियों की छुट्टी करने पर किसी को हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। विशेषकर तब जब एक तरफ तो आप सरकार की, उसकी नौकरशाही की आलोचना करते हैं और उसकी कार्यक्षमता में गिरावट का रोना रोते हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधा के अभाव की बात करते हैं और फिर जैसे ही सरकारी दफ्तरों में बैठे निकम्मे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत होती है तो कुछ लोग उनके बचाव में लग जाते हैं। इस क्रम में लोग कई बार सरकार पर निजीकरण करने का आरोप भी लगाते हैं। शासन या सत्ता समाज के कल्याण के लिए होती है। उसे नौकरशाही करे या निजी क्षेत्र करे, अंतिम आदमी को नागरिक हक, न्याय और सुविधाएं चाहिए, ईमानदारी चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। जो भी सरकार इसे निष्पक्षता से करे उसका साथ देने की जरूरत है। यह उल्लेखनीय है कि 16 आइएस अफसरों को पुरस्कृत करने की चयन प्रक्रिया में देश के नामी-गिरामी लोग जुड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरएम लोढ़ा उस चयन समिति के अध्यक्ष थे और पूर्व नौकरशाह हबीबुल्ला, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, पूर्व कैबिनेट सचिव चंद्रशेखर सदस्य थे। उन्होंने पांच मानदंडों पर देशभर से आई संस्तुतियों पर विचार किया और फिर एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड के लिए उन्हें चुना है। हाल में उठाए गए कई कदम नौकरशाही में बदलाव के संकेत दे रहे हैं। जैसे इन्हें पुरस्कृत किया गया है वैसे ही कुछ दिनों पहले कस्टम, इनकम टैक्स, पुलिस आदि विभाग के दर्जनों अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त भी किया गया है। काफी अरसे के बाद उन अधिकारियों को भी नौकरी से निकाल दिया गया है जिन्हें सरकार ने विदेश भेजा तो था प्रशिक्षण के लिए, लेकिन वे वर्षों से बिना बताए गायब थे। ऐसे अधिकारियों को राष्ट्रीय हित में बिना किसी रियायत के तुरंत सबक सिखाने और दूसरों को भी संदेश देने की जरूरत है।

ठीक जिस वक्त कुछ कर्मठ अफसरों को पुरस्कृत किया जा रहा था उसी समय नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में क्या-क्या सुधार अपेक्षित हैं, उस पर दिल्ली में विचार मंथन चल रहा था। मेरा मानना है कि न केवल भर्ती प्रक्रिया, बल्कि सेवाकालीन प्रशिक्षण आदि को भी फिर से परिभाषित करने की जरूरत है जिससे नौकरशाह, मालिक के बजाय जनता के सेवक के रूप में प्रतिष्ठित हो सकें। कस्तूरीरंगन रिपोर्ट ने भी इसी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि हमारे नौकरशाह अंग्रेजी के दंभ में भारतीय जनता से लगातार दूर रहने की कोशिश करते हैं और गुमान रखते हैं। अब समय आ गया है कि नौकरशाही को जनमुखी बनाया जाए।

(लेखक रेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सोच

जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़ी सोच जरूरी है, ऐसा नहीं है कि जो लोग बड़ा नहीं सोचते, वे सोचते ही नहीं। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सोचता न हो। मेरा मानना है कि अगर आप सोच ही रहे हैं तो क्यों न बड़ा सोचें। नेपोलियन हिल के अनुसार, 'दुख और गरीबी स्वीकार करने के लिए जितना प्रयास अपेक्षित है, जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए उससे अधिक प्रयास की जरूरत नहीं है।' आपको बस एक संकल्प लेना है कि भव्य विचार रखने हैं। यह एक बर्गर और एक फल के बीच चयन करने जितना आसान है। आप दोनों ही चीजों को खा सकते हैं। आपको बस यह फैसला करना है कि आपको क्या चाहिए।

जहां जीवन है, वहां भली-बुरी दोनों प्रकार की घटनाओं का आना-जाना लगा ही रहता है। रात और दिन की भांति सुख-दुख के क्रम को रोका नहीं जा सकता। यदि व्यक्ति प्राप्त अनुकूलताओं की ओर ध्यान दे तो उसे अनुभव होगा कि कुछेक वस्तुओं का अभाव होने पर भी जितना कुछ उपलब्ध है वह कम नहीं है। विश्व में ऐसे असंख्य व्यक्ति हैं, जिन्हें संभवतः इतना ही प्राप्त नहीं है, जितना अभी मेरे पास है, फिर क्यों मुंह लटकाए फिर रहा हूं। व्यक्ति का ध्यान जब अपनी प्रतिकूलताओं पर ही टिका रहता है तब वह जिधर देखेगा, उधर अभाव ही दिखाई देगा। इससे कुछ लाभ वाली स्थिति का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे में चित खिन्नता का अनुभव करेगा और निराशा ही हस्तगत होगी। अपनी आदतों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जीवन के उजले पक्ष को देखें और उससे कुछ प्रेरणा लें तो जीवन में बहुत कुछ पाया जा सकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है।

'योर बेस्ट लाइफ नाउ' में जोएल ओस्टीन कहते हैं-'आपको अपने दिमाग में यह बात रखनी चाहिए कि आप परम परमात्मा की संतान हैं और महान चीजों के लिए बनाए गए हैं। ऐसा करने के लिए उसने आपको काबिलियत, अंतर्दृष्टि, प्रतिभा, बुद्धि और अलौकिक शक्तियां दी हैं।'

ललित गर्ग

भारतीय भाषाओं की अनदेखी

अनीश कुमार

दुख की बात है कि आज देश का एक वर्ग रोजमर्रा के प्रयोग से अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बनाने पर तुला है

भारत को समझने और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय भाषाएं सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। दरअसल भाषाएं भावी पीढ़ी के लिए केवल साक्षरता के लिए ही जरूरी नहीं हैं, बल्कि भाषाओं में निहित ज्ञानराशि को समझने का सशक्त जरिया भी हैं। यह ज्ञानराशि ही असली भारत है। इसमें आम कामगारों के, किसानों के और आधुनिक पेशवरों के अभ्यासजन्य और अनुभवजन्य ज्ञान संचित हैं। विडंबना है कि यह ज्ञानराशि राशि धीरे-धीरे हमारी शिक्षा की मुख्यधारा में संकुचित हो चुकी है। इसका ही दुष्परिणाम है कि भावी पीढ़ी अपने आनंद और पीड़ा के रंगों का चुनाव गंगा-जमुना के मैदानों, अरावली या दंडाकारण्य आदि की लोकसंस्कृति से, केरल और तमिलनाडु के मृदु-कठोर भावों से कर पाने में सक्षम नहीं है।

दुर्भाग्य यह है कि अपनी इस अक्षमता का उसे भान तक नहीं है, क्योंकि वह अपनी जरूरतों को दूसरों की भाषा से पूरा करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इस तरह की एक पूरी पीढ़ी ने देखा है कि अंग्रेजी न आने के कारण उसे कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह पूरी पीढ़ी मां-बाप की भूमिका में अपने बच्चों को उसी अंग्रेजी का संस्कार देना चाह रही है जिसकी कमी से वे जूझते रहे। दुकान से लेकर डाइनिंग टेबल तक बच्चों को अंग्रेजी के शब्दों और 'आदतों' का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस अभ्यास से लगभग हर अभिभावक खुद को आश्वस्त कर रहा है कि उसके बच्चे को आने वाले जीवन में किसी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी दशा में बार-बार यही सवाल उपजता है कि क्या अभिभावक अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी भाषा और माध्यम की शिक्षा के बरक्स मातृभाषा में शिक्षा को स्वीकार करेंगे? यह सवाल केवल अभिभावकों के स्तर तक ही सीमित नहीं है।

इसके समांतर अगला प्रश्न है कि क्या स्कूल नामक संस्था भारतीय भाषाओं में ज्ञान रचना के लिए तैयार है? इन दोनों ही सवालों के लिए अक्सर 'औपनिवेशिक' प्रभाव की दुहाई देते हुए हम पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन हमें अपनी असफलता को भी स्वीकारना होगा कि आजाद भारत में मजबूत भाषा नीतियों के बावजूद पाठ्यचर्या के माध्यम और भाषा के रूप में भारतीय भाषाएं उपेक्षित हैं।

इसका सरलीकृत कारण नीति का कमजोर क्रियान्वयन नहीं है, बल्कि आर्थिक अवसरों, सामाजिक प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक बड़प्पन के नाम पर लोक जीवन का अंग्रेजीकरण है। इसके प्रभाव में भारतीय भाषाएं धीरे-धीरे अनौपचारिक कार्य-व्यापार तक सीमित होती जा रही हैं। वर्तमान में भाषा की एक नई समस्या है कि एक वर्ग बोलचाल, रोजमर्रा के व्यवहार और औपचारिक प्रयोग से अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बनाने पर तुला है। इसी वर्ग के जैसा बनने के लिए शेष समाज अपने 'संस्कृतिकरण' के लिए उनकी भाषा को अपना रहा है। उक्त के आलोक में आज इस सवाल का उत्तर खोजा जाना चाहिए कि अंग्रेजी के प्रभाव से निपटने के लिए भारतीय भाषाओं को कैसे समर्थ बनाया जाए?

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

मेलबाक्स

निष्पक्ष होकर कार्य करें जांच एजेंसियां

जांच एजेंसियों की जवाबदेही भी जरूरी शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने सीबीआइ तथा ईडी जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसियों को निष्पक्ष एवं राजनीतिक दबाव से परे रहकर कार्य करने पर बल दिया है, जो कि वर्तमान परिदृश्य में बेहद जरूरी एवं प्रासंगिक भी है। सरकार बदलने पर पूर्व की सरकारों में रहे मंत्रियों पर स्वतंत्र जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई करना शक पैदा करता है, सत्ता में रहते हुए किसी मंत्री पर प्रभावी कार्रवाई ना होना ही शक का कारण भी है। इन्हें सत्तासीन दल के मंत्रियों का भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखाई देता? जिस दिन सत्ता में रहते हुए भ्रष्ट मंत्रियों तथा भ्रष्ट नेताओं पर उक्त जांच एजेंसियां प्रभावी कार्रवाई करना शुरू कर देंगी, जनता का विश्वास इन जांच एजेंसियों पर बढ़ जाएगा। यह कटु सच्चाई है कि आजकल जांच एजेंसियां निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर पा रही हैं, बल्कि सत्तासीन दल की कठपुतली की तरह कार्य करती हैं, जो कि जनता के अविश्वास का मुख्य कारण है। सरकारों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे जांच एजेंसियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रहने दें, उनका दुरुपयोग ना करें और न होने दें ताकि सरकार और जांच एजेंसियों पर आम जनमानस का विश्वास कायम हो सके।

सर्वजीत आर्या, कन्नौज

भारत और यूएई संबंध

भारतीय प्रधानमंत्री इन दिनों दो खाड़ी देशों संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के दौरे पर थे। यूएई भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। यह उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनसे भारत का व्यापार संतुलन की स्थिति में है। यदि यूएई की तुलना में हम चीन के साथ अपने व्यापारिक आंकड़ों को देखें तो जितना कुल व्यापार हम यूएई के साथ करते हैं उतना हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा है। भारत-यूएई के द्विपक्षीय संबंध आज के समय में सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं, पिछले चार वर्षों में यूएई भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक, सामरिक साझेदार बन चुका है। आने वाले समय में भारत और यूएई के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। भारत-यूएई के संबंधों का अंदाजा जम्मू कश्मीर के मामले पर यूएई के वक्तव्य से लगाया जा सकता है, जिसमें यूएई उन चुनिंदा देशों में शामिल पहला देश था जिसने भारत की कश्मीर नीति का समर्थन किया। यूएई कई महत्वपूर्ण इस्लामिक संगठनों का महत्वपूर्ण सदस्य है, जिनमें ओआइसी शामिल है जहां पर पाकिस्तान भारत को संयुक्त राष्ट्र में घेरने के लिए असफल कूटनीतिक चाल चलता रहा है। यूएई का इस तरह जम्मू कश्मीर मुद्दे पर खुलकर सामने आना और भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करना उद्दंड पाकिस्तान को करारा तमाचा है। मोदी की यह तीसरी यूएई यात्रा है। बहरीन और यूएई ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित कर इस यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया है।

kulindaryadav5412@gmail.com

कांग्रेस को ऊर्जा चाहिए

लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस आज दोयम दर्जे की पार्टी बन गई है। चुनाव में बार-बार पराजय के बाद आत्मविश्वास खो चुकी इस पार्टी के एक के बाद एक नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। इससे इसकी साख और खराब हो रही है। हालात यह हैं कि इस समय विपक्ष के नाम पर कोई प्रभावशाली नेता नहीं दिख रहा है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। कांग्रेस से लोगों को बड़ी उम्मीद हैं, लेकिन पार्टी इस दिशा में कुछ करती नजर नहीं आ रही है। पार्टी को कम से कम अपना एक स्थायी अध्यक्ष तो चुन ही लेना चाहिए, जो पार्टी में नई ऊर्जा भर सके।

दीपांशु अरोड़ा, दिल्ली

पीवी सिंधू की शानदार जीत

भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधू ने एक बार फिर से देश के सामने चुनौती रख दी है कि किसी भी खेल में हुनर की कमी नहीं। बस जरूरत है उनको पहचानने और निखारने की। बैडमिंटन के ऊंचे आकाश पर चमकते सितारे पर देश को गर्व क्यों न हो। कड़ी मेहनत और लगन से ही सिंधू ने ये ऊंचाई पाई है। अपनी जीत को अपनी मां को समर्पित कर सिंधू ने नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम की है। देश को अपने इस होनहार खिलाड़ी से बार-बार ऐसी जीत की उम्मीद रहेगी।

mkmishra75@yahoo.in

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया